

हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 44

देहरादून, बुधवार, 03 अगस्त, 2022

मूल्य : एक रुपया

पृष्ठ : 08

महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मिली
स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण

3

कर्णप्रयाग-ऋषिकेश रेल प्रोजेक्ट की टनल की सुरक्षा दीवार धंसी

मूर्गम विज्ञानियों की रिपोर्ट आने तक रोका निर्माण कार्य

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

कर्णप्रयाग (चमोली) / ऋषिकेश : पहाड़ी से हुए भूस्खलन और वर्षा के पानी से ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की सिवई में निर्माणाधीन टनल के मुहाने पर बनी सुरक्षा दीवार धंस गई। टनल को नुकसान नहीं हुआ लेकिन सुरक्षा दीवार का लगभग 15 मीटर हिस्सा दरक गया। टनल पर दो दिन से काम बंद था।

भू-विज्ञानी और रेलवे के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिए हैं। धंसाव वाले स्थान का ट्रीटमेंट करने के बाद ही यहां काम शुरू किया जाएगा। सेवई ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का अंतिम स्टेशन है। इससे पहले लगभग सवा छह किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है।

कर्णप्रयाग से सात किलोमीटर दूर निर्माणाधीन गौचर (रानो) रेल टनल का निर्माण किया जा रहा है। मंगलवार सुबह लगभग छह बजे निर्माणाधीन टनल के बायीं तरफ सुरक्षा दीवार धंस गई। इसके कारण टनल के ऊपरी हिस्से से गुजर रहे मोटर मार्ग का 25 मीटर बड़ा हिस्सा भी धंस गया। रेल



विकास निगम के साइट इंजीनियर लोकेश ने बताया कि भूस्खलन के कारण टनल के साइड स्लोप (सुरक्षा दीवार) धंस गए। टनल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है।

इसका ऊपरी तथा निचला हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक तौर पर सामने आ रहा है कि टनल के ऊपरी क्षेत्र में मोटर मार्ग और पहाड़ी से वर्षा के पानी के साथ काफी मलबा टनल के मुहाने पर आया। इसकी वजह से टनल के मुहाने वाले हिस्से से भू-धंसाव की स्थिति पैदा हुई है। ऋषिकेश-

कर्णप्रयाग रेल परियोजना के वरिष्ठ प्रबंधक ओमप्रकाश मालगुड़ी ने बताया कि घटना के बाद रेल विकास निगम के अधिकारियों और भूगर्भ विज्ञानियों ने सिवई पहुंचकर मौका मुआयना किया। भूस्खलन के कारणों और वहां की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में निर्माण कार्य तत्काल शुरू नहीं किया जा सकता है। चूंकि टनल के अंदर काम करने में सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भूगर्भीय सर्वे रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

346 नए कोरोना पॉजिटिव मिले दो की मौत, हरिद्वार जिला जेल में 43 कैदी भी संक्रमित

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 346 नए संक्रमित मिले हैं जबकि तीन मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना की संक्रमण दर भी बढ़कर 11 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। देहरादून में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, मंगलवार को सामने आए 346 नए मामलों में सर्वाधिक 188 देहरादून के हैं। इसके अलावा, हरिद्वार के 53, नैनीताल के 40, उत्तरकाशी के 21, अल्मोड़ा के आठ, पौड़ी और टिहरी में सात-सात, ऊधमसिंह नगर में छह, बागेश्वर और चमोली में पांच-पांच, रुद्रप्रयाग के तीन, चंपावत के दो और पिथौरागढ़ का एक मामला शामिल है। जबकि तीन कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इनमें एम्स ऋषिकेश, श्री महंत इंदिरेश अस्पताल और एसटीजीएच हल्द्वानी का एक-एक मरीज शामिल है। वहीं मंगलवार को प्रदेश में 35,178 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर भी तेजी से बढ़ती जा रही है। दो जुलाई को प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 3.21 प्रतिशत थी जो कि 15 जुलाई को बढ़कर 6.95 पहुंच गई थी। मंगलवार को संक्रमण



की दर 11.91 प्रतिशत दर्ज की गई।

प्रदेश में मंगलवार को 85 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। अब 1925 एक्टिव केस हैं। इनमें सर्वाधिक 1137 मामले देहरादून के हैं। इसके अलावा नैनीताल के 274, हरिद्वार के 155 मामले शामिल हैं। सबसे कम सात एक्टिव केस पिथौरागढ़ के हैं।

हरिद्वार की जिला जेल में 43 कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। जेल में 28 व 29 जुलाई को हेपेटाइटिस की जांच के लिए लगाए गए शिविर में कैदियों के कोरोना सैंपल लिए गए थे। जिनकी गजांच रिपोर्ट 43 कैदियों आई है। जेल अधीक्षक मनोज आर्य का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी है। जिला सर्विलांस ऑफिसर पंकज जैन ने बताया कि 43 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

मंत्री महाराज से मिलने घर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से उनके आवास पर आकर शिष्टाचार भेंट की। भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंगलवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से उनके म्युनिस्पल रोड स्थित आवास

पर आकर शिष्टाचार भेंट की।

सतपाल महाराज ने महेंद्र भट्ट को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने तथा संगठन की नींव को और अधिक मजबूती मिलेगी।

15 अगस्त से पहले मिलेगी 449 प्रवक्ताओं को तैनाती : डॉ० धन सिंह रावत

दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में मिलेगी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति

आशीष तिवारी की विशेष रिपोर्ट न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आगामी 15 अगस्त से पहले विभिन्न विषयों के 449 प्रवक्ताओं को तैनाती दी जायेगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित इन शिक्षकों को पर्वतीय एवं दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में प्रथम तैनाती दी जायेगी। जिसके निर्देश विभाग के उच्चाधिकारियों को दे दिए गये हैं। गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को अनुरोध के आधार पर इच्छित स्थानों पर शीघ्र तैनाती के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये हैं।

शिक्षा मंत्री डॉ० धन सिंह रावत ने शिक्षा महानिदेशालय देहरादून में विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में डॉ० रावत ने राज्य लोक सेवा आयोग से विभिन्न विषयों में चयनित 449 प्रवक्ताओं को आगामी 15 अगस्त से पहले नियुक्ति देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।

उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों को सूबे के पर्वतीय एवं दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में 5 साल के लिये तैनाती दी जायेगी। जिससे दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जायेगी साथ ही पठन-पठान भी सुचारु हो जायेगा। डॉ० रावत ने बताया कि सामान्य शाखा के अंतर्गत दुर्गम श्रेणी

**बीमार
शिक्षकों को
अनुरोध के आधार
पर इच्छित स्थान पर
तैनाती के निर्देश**



के स्कूलों में अंग्रेजी विषय के 64, हिन्दी के 81, संस्कृत के 18, भौतिक विज्ञान के 46, रसायन विज्ञान के

42, गणित के 6, जीव विज्ञान के 35, नागरिकशास्त्र के 38, अर्थशास्त्र के 74, इतिहास के 8, भूगोल के 17, समाजशास्त्र के 6, कला, मनोविज्ञान एवं कृषि के एक-एक शिक्षक की तैनाती की जायेगी। बालिका इंटर कॉलेजों में हिन्दी विषय की 2, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अर्थशास्त्र की 3-3 शिक्षिकाओं को नियुक्ति दी जायेगी। विभागीय मंत्री ने बताया कि ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से

ग्रसित हैं उन्हें अनुरोध के आधार पर इच्छित स्थानों पर तैनाती दी जायेगी, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गए हैं।

उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से रोगग्रस्त शिक्षक अपने उपचार के साथ-साथ शैक्षणिक कार्य का निर्वहन भी कर सकेंगे। बैठक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, निदेशक माध्यमिक आर०के०कुंवर, निदेशक सीमैट सीमा जौनसारी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा वंदना गर्ब्याल, अपर निदेशक आर०के० उनियाल, भूपेन्द्र नेगी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

क्या आप जानते हैं, टीवी सीरियल को डेली सोप क्यों कहते हैं?



महविशा की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

1984 में देश का पहला सीरियल शुरू हुआ नाम था हम लोग (Hum Log). मिडिल क्लास पर बने इस सीरियल ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ दी थी. इस सीरियल का हर कलाकार एक सितारा था. इस सीरियल को देखने के लिए ना जाने कितने लोगों ने टीवी खरीद डाले थे. देखते ही देखते और भी सीरियल बनने लगे. हम लोग के बाद बुनियाद (1986-87), रामायण (1987-88) और महाभारत (1988-89) जैसे कई टीवी शो टेलिकास्ट हुए... पर क्या आप ये जानते हैं कि टीवी सीरियल को डेली सोप क्यों कहा जाता है. नहीं, तो हम आपको बताएंगे कि आखिर टीवी सीरियल्स को डेली सोप के नाम से क्यों जाना जाता है.

टीवी का सफर करीब 96 साल पुराना है. नौ दशक पहले कभी भारी-भरकम डिब्बे के रूप में दिखने वाला इडियट बॉक्स आज काफी स्लिम हो गया है. टेक्नोलॉजी तो ऐसी विकसित हुई है कि

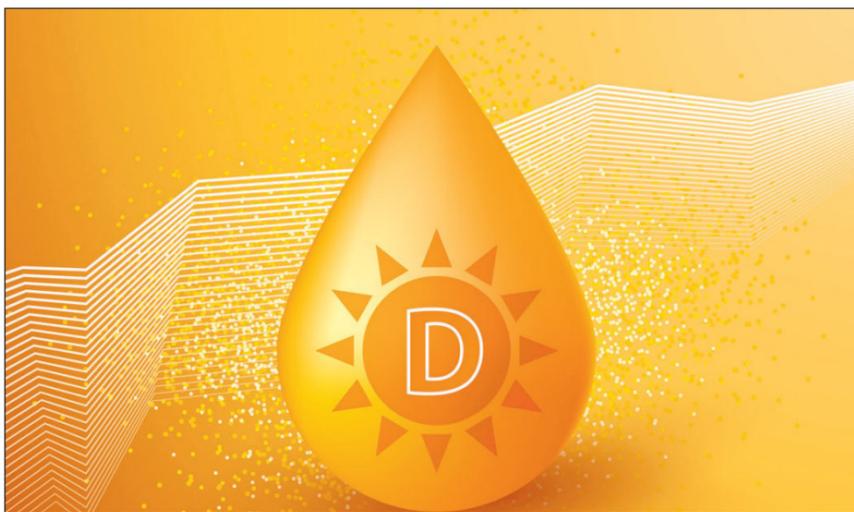


आज तो हमारे बोलने भर से ही चैनल बदल जाते हैं दरअसल बात काफी पुरानी है. 1920 के दौर में रेडियो स्टेशन को आसानी से विज्ञापन नहीं मिलते थे. इन ऐड के लिए रेडियो को काफी महनत करनी पड़ती थी. घरेलू सामान के ऐड आसानी से मिल सकते थे पर रेडियो की टारगेट ऑडियंस महिलाएं बन रही थीं. उस वक्त P&G कंपनी यानी प्रॉक्टर एंड गैबल ने अपने एक प्रोडक्ट के लिए रेडियो शो स्पॉन्सर किया. 1933 में ये शो आया जिसका नाम था 'Ma Perkins' जिसमें उनके प्रोडक्ट Oxydol के लिए विज्ञापन देना था. इन शो के बीच बीच में Oxydol का ऐड आने लगा और फिर ये जबरदस्त तरीके से हिट हो गया.

इसको देखते हुए रेडियो शो बनने शुरू हो गए जिनमें बीच बीच में ऐड आ जाया करते थे. इस वजह से इन कार्यक्रमों को सोप ओपेरा (Soap opera) या डेली

सोप (Daily Soap) कहा जाने लगा. बाद में रेडियो की जगह टीवी ने ले ली. मगर ये तरीका और नाम वैसा ही. इसी कारण इन्हें आज भी डेली सोप ही कहा जाता रहा... वहीं इसको लेकर एक और धारणा भी है. कहा जाता है कि जब यूएसए में ओपेराज ने टीवी की दुनिया में अपना पहला कदम रखा, तो साबुन बनाने वाली यानी सोप कंपनियों में उन्हें स्पॉन्सर करने की होड़-सी लग गई. साबुन बनानेवाली सभी कंपनियां चाहती थीं कि उनका साबुन यानी उनका सोप ओपेराज को स्पॉन्सर करे. साबुन कंपनियों की इस होड़ को देखते हुए ओपेराज का नाम सोप ओपेरा पड़ गया. हालांकि आज भी टीवी शो को स्पॉन्सर करने के लिए कंपनियों में होड़ लगी रहती है. किसी सीरियल का ट्रेलर आया नहीं कि कंपनियों ने बोली लगाना शुरू कर दिया.

जानिए कैसे बनता है हमारे शरीर में विटामिन डी



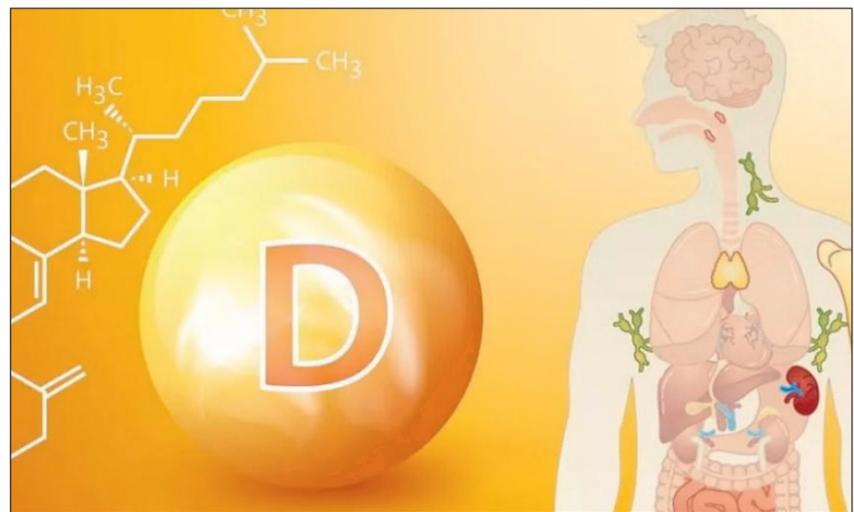
महविशा की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

विटामिन डी हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है. इस विटामिन को त्वचा सूर्य के प्रकाश के जरिए पैदा करता है. यह एकमात्र विटामिन है जो शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य (Bone Health) के लिए बहुत जरूरी हैं. इसके अलावा विटामिन डी (Vitamin D) कैंसर के जोखिम को

कंट्रोल करता है, संक्रमण को नियंत्रित करता है और सूजन को कम करने के लिए जाना जाता है. विटामिन डी को कई स्वास्थ्य स्थितियों जैसे हड्डियों के स्वास्थ्य और मांसपेशियों की ताकत, कैंसर, हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज, इम्यून फंक्शन के साथ जोड़ा गया है. कई अध्ययनों ने डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को कंट्रोल करने और हड्डियों के स्वास्थ्य और इम्यूनिटी में सुधार में इसकी भूमिका की पुष्टि की है. विभिन्न

शोध अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन डी कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कोलन, प्रोस्टेट और स्तन कैंसर को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकता है.

शरीर में विटामिन डी कैसे बनता है? विटामिन डी तब बनता है जब मानव त्वचा पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है. जब त्वचा सूरज के संपर्क में आती है तो 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक एक स्टेरॉयड टूट जाता है. इससे विटामिन डी का निर्माण होता है.



कैसे होती है विटामिन डी की कमी की अधिक संभावना?

जो लोग पूरे कपड़े पहनते हैं और त्वचा को धूप में निकलने के लिए नहीं छोड़ते हैं. जो लोग सनस्क्रीन का अत्यधिक उपयोग करते हैं वे त्वचा की विटामिन डी को संश्लेषित करने की क्षमता को सीमित कर देते हैं. जो लोग बाहर ज्यादा समय नहीं बिताते हैं जिनकी त्वचा का रंग गहरा होता है जो बूढ़े हैं; ये लोग आमतौर पर घर के अंदर रहते हैं और इनका 7-

डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है. जो लोग मोटे हैं. जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है क्रोनिक किडनी या लीवर की स्थिति वाले लोग.

विटामिन डी की कमी के लक्षण
विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में दर्द, थकान और अवसाद होता है. विटामिन डी की कमी के गंभीर मामलों में हड्डियों में दर्द के लक्षण दिखाई दे सकते हैं. विटामिन डी की कमी को डिमेंशिया के लिए एक जोखिम कारक भी कहा जाता है.

महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मिली स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस शिष्टाचार भेंट के दौरान राष्ट्रपति एवं विधानसभा अध्यक्ष के बीच विभिन्न समसामयिक

विषयों को लेकर चर्चा वार्ता भी हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के सर्वोच्च एवं गरिमामय पद पर रहते हुए द्रौपदी मुर्मू जी के संरक्षण में लोक कल्याण एवं विकास सहित महिला सशक्तिकरण की दिशा में गति मिलेगी और भारत विश्व पटल पर नई पहचान स्थापित करेगा।



नैनीताल जिला की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने ली जिला योजना समिति की बैठक

जिला योजना की बैठक में 51 करोड़ 51 लाख की धनराशि हुई अनुमोदित

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हल्द्वानी: प्रसार प्रशिक्षण केंद्र बागजाला में जनपद के सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2022-23 के लिए प्रभारी मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में रुपये 51 करोड़ 51 लाख का परिव्यय जिला योजना समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया। जनपद के लिए अनुमोदित परिव्यय में से सामान्य के लिए 41 करोड़ 04 लाख, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 09 करोड़ 88 लाख व अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए 59 लाख का परिव्यय अनुमोदित है।

■ बैठक में सचिव, जिला योजना समिति/जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने समिति को अवगत कराया गया कि जनपद में कुमाऊँनी बोली को बढ़ावा देने के लिये रामनगर, कोटाबाग व हल्द्वानी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुमाऊँनी बोली को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में समावेशित कर शुरू किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा कुमाऊँनी बोली का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इससे बोली का व्यापक प्रचार प्रसार, बोली का संरक्षण, शिक्षा जगत में बोली का उन्नयन होगा।

■ जनपद में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा व पलायन को रोकने के लिए सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके तहत गांव के गांव लिए जाएंगे। सामुदायिक पर्यटन के अंतर्गत पर्यवरण व प्रकृति के अनुरूप घरों का निर्माण किया जाएगा।

■ विकास खंड रामगढ़ से औद्योगिक पर्यटन को शुरू किया जाएगा। औद्योगिक पर्यटन के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा व पर्यवरण संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए रामगढ़ में फलपट्टी विकसित की जा रही है।



■ हल्द्वानी व उसके आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर में वृद्धि हेतु लघु सिंचाई विभाग द्वारा जिला योजना से 23 स्थानों पर रिचार्ज शाफ्ट निर्मित किये जायेंगे। प्रति रिचार्ज शाफ्ट से प्रति वर्ष लगभग 52 लाख लीटर भूजल स्तर में वृद्धि होगी। इस सम्बंध में जनपद प्रभारी मंत्री ने आगामी वर्ष में रिचार्ज से हुए लाभ की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई को दिए।

बैठक में प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने समस्त विभागीय अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि आम जन को योजनाओं की पूर्ण जानकारी हो सके व योजनाओं से लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने स्थानीय प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन करने के निर्देश दिए। कहा कि आगामी जिला योजना हेतु त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के अनुसार की

योजनाओं को चिन्हित किया जाए। कहा कि योजनाओं का मूल भावना को साकार रूप दिया जा सके इसके लिए जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों आपसी समन्वय से समाज हित में कार्य को पूर्ण करें।

■ जनपद हेतु अनुमोदित रुपये 51 करोड़ 51 लाख में से पर्यटन को 6 करोड़ 65 लाख, उद्यान को 06 करोड़, निजी लघु सिंचाई को 02 करोड़ 20 लाख, कृषि को 01 करोड़ 20 लाख, लोनोवि को 03 करोड़ 50 लाख, माध्यमिक शिक्षा को 02 करोड़ 20 लाख, स्वास्थ्य को 01 करोड़ 70 लाख, प्राथमिक शिक्षा को 01 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत बेला तोलिया, विधायक डा0 मोहन सिंह

बिष्ट, दीवान सिंह, सरिता आर्या, सुमित हृदयेश, ब्लाक प्रमुख कमलेश कैड़ा, आशा देवी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद दरमवाल के साथ ही जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, एसएसपी पंकज भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी डा0 संदीप तिवारी, प्रभागीय वनाधिकारी चन्द्रशेखर, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 भागीरथी जोशी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 बीएस जंगपांगी, मुख्य उद्यान अधिकारी डा0 नरेन्द्र कुमार, जिला अर्थसंख्याधिकारी डा0 मुकेश नेगी, अपर जिला संख्याधिकारी बीएस राणा, कमल मेहरा, सुरेश लाल, एच एस मिश्रा, निजी सचिव एल एस नगरकोटी, के साथ ही जिला पंचायत सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।



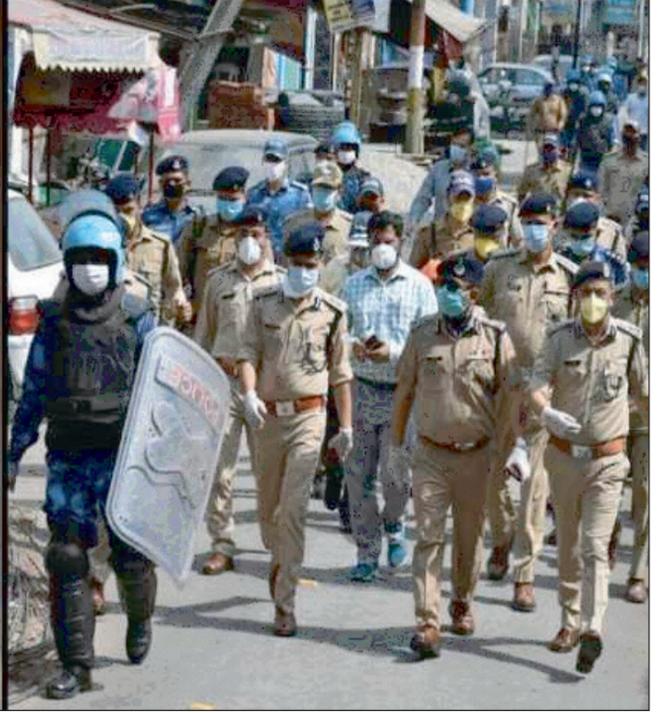
डीजीपी अशोक कुमार का भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सरकारी/निजी भूमि व भवनों पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड ने ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिला बदर करने, गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने तथा इनकी हिस्ट्रीसीट खोले जाने एवं इनके लाईसेन्सी शस्त्रों को भी निरस्त करने हेतु समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया है।

चिन्हित भू-माफियाओं का थाना, जनपद तथा परिक्षेत्र स्तर पर रजिस्टर (डेटाबेस) तैयार कर उसे अध्यावधिक रखने एवं अन्य जनपदीय प्रभारियों से समन्वय स्थापित कर इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की मासिक सूचना नियमित रूप से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

ऐसे भू-माफियाओं के विरुद्ध निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जनता द्वारा की गयी शिकायत पर तत्काल अभियोग



पंजीकृत करने तथा सरकारी एवं लावारिस भूमि, नदी, सार्वजनिक सड़क

आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को सूचित करने साथ ही जनपदीय पुलिस

प्रभारियों को जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर तत्काल प्रथम सूचना दर्ज

कराकर विधिक कार्यवाही हेतु भी निर्देशित किया गया है।

6 बच्चों की बूढ़ी प्रेमिका से 9 बच्चों के बुजुर्ग ने हरिद्वार में की शादी

फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उफ़फ़ ये इश्क़ क्या न कराये ... कभी खुशी दे तो कभी जग हँसाई कराये ... जी हों हिंदुस्तान में ऐसा भी होता है जैसा अमरोहा में बुजुर्ग प्रेमियों के अजब प्रेम की गजब कहानी से आपको हम बताने जा रहे हैं। 9 बच्चों को बुजुर्ग पिता 6 बच्चों की बूढ़ी मां के साथ पहले तो गंगा नहाने हरिद्वार पहुंचे और फिर इस बुजुर्ग प्रेमी युगल ने हरिद्वार गंगा स्नान के बाद शादी

करने के लिए फरार हो गए हैं।

यह प्रेम कहानी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों में करीब 21 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के फरार होने को लेकर रविवार को गांव में पंचायत भी की गई, जिसमें दोनों तलाश करने का फैसला लिया गया है। वहीं, इस मामले को लेकर प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि तहरीर मिलने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। यह मामला अमरोहा के सैदनगली थाना क्षेत्र



के एक गांव का है। परिजनों के मुताबिक, 29 जुलाई को गांव से 15 लोग हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गए थे। उन्हीं में ये दोनों भी शामिल थे। गंगा स्नान के बाद सभी लोग गांव लौट आए हैं, लेकिन बुजुर्ग प्रेमी युगल अपनी नई पारी खेलने के लिए फरार हो गए हैं। उनके इस कृत्य से उनके बेटे-बेटियां शर्मसार हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि

बुजुर्ग प्रेमी की पत्नी का 29 वर्ष पहले निधन हो गया था। जबकि बुजुर्ग प्रेमिका के पति की भी 30 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। बुजुर्ग प्रेमी के 9 बच्चे हैं तो बुजुर्ग प्रेमिका के 6 बच्चे हैं, जो सभी जवान हैं।

बता दें कि बुजुर्ग प्रेमी की प्रेमिका रिश्ते में उसकी चाची है। दोनों का अचानक गायब

होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की भनक परिजनों को पहले से थी। लेकिन, उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी वह फरार हो सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बुजुर्ग प्रेमी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है।

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामला : एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक जारी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पुख्ता साक्ष्यों और बयानों के आधार पर कनिष्ठ सहायक हिमांशु कांडपाल, रामनगर न्यायालय, जिला नैनीताल को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त हिमांशु कांडपाल पुत्र प्रयाग दत्त कांडपाल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कांडागुट पोस्ट ऑफिस दौलीगार ब्लॉक धौलादेवी जिला अल्मोड़ा हाल पता कनिष्ठ सहायक एसीजेएम न्यायालय रामनगर को 2 अगस्त मंगलवार की शाम गहन पूछताछ के बाद पुख्ता साक्ष्य के आधार पर एसटीएफ कार्यालय में गिरफ्तार किया गया है अभियुक्त द्वारा अपने सगे जीजा मनोज जोशी (पीआरडी) के माध्यम से अन्य अभियुक्त महेंद्र चौहान एवं दीपक शर्मा के साथ मिलकर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र लीक कर



डीएम सोनिका का विकासनगर तहसील में रियलिटी चेक, दिए निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून की जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने तहसील विकासनगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय, एसडीएम कोर्ट, कार्यालय, ई डिस्ट्रिक्ट सेवा केंद्र का अवलोकन किया। तहसील से पहले ही वाहन रोककर पैदल आम लोगों की तरह तहसील पहुंची।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तहसील में आने वाले आगंतुकों से तहसील में आने का कारण पूछा इस दौरान कई फरियादियों द्वारा आज तहसील दिवस में अपनी समस्याओं के निस्तारण को लेकर तहसील आने का कारण बताया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाली समस्याओं को तहसील स्तर पर ही निस्तारित करने के निर्देश दिए साथ ही विकासनगर तहसील अंतर्गत आने वाले भूमि विवाद, अतिक्रमण, दाखिला खारिज आदि प्रकरणों की जांच कर निस्तारित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान भूमि डिमाकेशन प्रकरण



को लेकर एक महिला फरियादी जिलाधिकारी से मिली उन्होंने जिलाधिकारी से सेंट्रल होपटाउन सेलाकुई में वर्ष 2014 में क्रय की गई अपनी भूमि का डीमाकेशन कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने

उप जिलाधिकारी विकासनगर को मौके पर टीम भेजकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार विकासनगर को सख्त निर्देश

दिए कि तहसील में आने वाले लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तहसील स्तर पर ही उनकी समस्या को निस्तारण करें। साथ ही कहा कि तहसील स्तर की शिकायतें जिलाधिकारी स्तर पर नहीं आनी

चाहिए। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सप्ताह में तीन दिन न्यायालय में लंबित वादों के लिए निकालते हुए वादों के निस्तारण में तेजी लाना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी विकास नगर विनोद कुमार, सहायक निदेशक सूचना बंदी चंद्र नेगी, तहसीलदार विकासनगर मुकेश रमोला एवं तहसील के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एसओपी, विदेश यात्रा से लौटने वालों पर रखी जाएगी नजर...

महविश की रिपोर्ट - न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मंकीपाक्स को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। जिसके तहत सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सर्विलांस सिस्टम को सुदृढ़ करने को कहा गया है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई एसओपी

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों पर मंगलवार को उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की गई। एसओपी में एहतियात के तौर पर विदेश यात्रा से लौटने वालों में मंकीपाक्स के लक्षणों पर नजर रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

एसओपी में दिए गए निर्देश

एक केस मिलने पर भी उसे प्रकोप माना जाएगा कोई केस मिलने के बाद तुरंत कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी संदिग्ध के मिलने पर तुरंत जिला सर्विलांस यूनिट को सूचना दी जाएगा इड लाइन के मुताबिक सैपल भेजे जाएंगे रिपोर्टिंग टीम द्वारा जांच की जाएगी



संभावना को देखते हुए टारगेटेड सर्विलांस स्थापित किया जाएगा लाइन वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए

सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट केरल व दिल्ली में मंकीपाक्स का

माामला मिलने के बाद उत्तराखंड के सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी में

मंकीपाक्स के लक्षण पाए जाते हैं तो सैपल लेकर जांच के लिए भेजे जाए और उसे आइसोलेशन में रखा जाए।

अगस्त में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, एक लॉन्ग वीकेंड भी, यहां देखें छुट्टियों की लिस्ट

फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अगस्त के महीने में बैंकों में बंपर छुट्टियां (Holidays in August) रहने वाली हैं। अगस्त में अलग-अलग जोन में बैंकों की शाखाएं 18 दिन बंद रहेंगी। अगस्त में एक लॉन्ग वीकेंड (Long Weekend) भी आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के दौरान तीन दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे। इस डिजिटल युग में लोगों के अधिकतर बैंकिंग (Banking) काम घर बैठे ही हो जाते हैं। इसके बावजूद खाता खुलवाने, चेक पेमेंट और लोन जैसे ऐसे कई काम हैं, जिनके लिए ग्राहकों को बैंक जाना पड़ जाता है। लेकिन क्या हो कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर चिलचिलाती धूप में बैंक ब्रांच (Bank Branch) जाएं और वहां जाकर आपको पता चले कि बैंक ही बंद है। इससे एक तो आपका बैंकिंग कार्य रुक जाएगा और आपको काफी परेशानी भी उठानी पड़ेगी। इससे बचने के लिए यह जरूरी है कि आप घर से निकलने से पहले बैंकों की छुट्टी की लिस्ट (Bank Holidays List) चेक कर लें और उसी अनुसार प्लान करें। आइए जानते हैं कि अगस्त (Bank Holidays in August 2022) में किस जोन की बैंक शाखाओं में किस दिन छुट्टी रहेगी।

लगातार तीन दिन बंद रहेंगे बैंक

अगस्त में लगातार तीन दिन बैंक बंद रहेंगे। दरअसल 13 अगस्त को दूसरे शनिवार के



चलते बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 14 अगस्त को रविवार के चलते बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। फिर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर बैंक बंद रहेंगे। इस तरह लगातार तीन दिन बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। बता दें कि बैंकों में हर रविवार के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है।

वीकेंड सहित इन तारीखों पर बंद रहेंगे बैंक

1 अगस्त, 2022 : सिक्किम में द्रुकपा त्शे-जी (Drukpa Tshe-zi) पर बैंक बंद रहेंगे।

7 अगस्त, 2022: रविवार (साप्ताहिक



अवकाश)8 अगस्त, 2022: मुहर्रम (अशूरा) के चलते जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।

9 अगस्त, 2022: मुहर्रम (अशूरा) के चलते त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हैदराबाद, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, लखनऊ, नई दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे।

11 अगस्त 2022: रक्षा बंधन के चलते गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

12 अगस्त, 2022: रक्षा बंधन के चलते महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगे।

13 अगस्त 2022: दूसरे शनिवार के चलते बैंक बंद रहेंगे।

14 अगस्त 2022: रविवार के चलते बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

15 अगस्त, 2022 : स्वतंत्रता दिवस के चलते बैंक बंद रहेंगे।

16 अगस्त, 2022 : पारसी नव वर्ष (शहंशाही) के चलते महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे।

18 अगस्त, 2022 : जन्माष्टमी के चलते उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

19 अगस्त, 2022 : जन्माष्टमी (कृष्ण जयंती) के चलते गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, जम्मू, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।

20 अगस्त, 2022 : श्री कृष्ण अष्टमी के चलते हैदराबाद में बैंक बंद रहेंगे।

21 अगस्त, 2022 : रविवार (साप्ताहिक अवकाश)29 अगस्त, 2022 : श्रीमंत शंकरदेव की तिथि के मौके पर असम में बैंक बंद रहेंगे।

27 अगस्त 2022: चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी।

28 अगस्त 2022: रविवार होने के कारण बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

31 अगस्त, 2022 : संवत्सरी (चतुर्थी पक्ष)/गणेश चतुर्थी/वरसिद्धि विनायक व्रत/विनायक चतुर्थी के मौके पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और गोवा में बैंक बंद रहेंगे।

Jio ने 5G लॉन्च से पहले बनाई बढ़त! जानें कैसे Airtel और Vi के दे दिया चकमा



फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने के मामले बाकी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले में बहुत हासिल कर ली है। बता दें कि जियो (Jio) 700 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम खरीदने वाला अकेला ऑपरेटर बन गया है। 5G के लिए बेहतरीन माने जाने वाले इस बैंड पर सभी ऑपरेटर की नज़र थी। लेकिन जियो ने इस प्रीमियम 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को अपने नाम करके 5G की दौड़ में शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है।

काफी फेमस है 700 मेगाहर्ट्ज बैंड दुनिया भर में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को 5जी के लिए प्रमुख बैंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इसे 5जी सर्विस के लिए प्रीमियम बैंड घोषित किया हुआ है। दुनिया भर में इस बैंड के लोकप्रिय होने की कई वजह हैं।

घनी आबादी में मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

टेलीकॉम सेक्टर पर नज़र रखने वाले रोहन धर्मीजा, 700 मेगाहर्ट्ज की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह इसकी बेहतरी इनडोर व आउटडोर कवरेज को मानते हैं। लो फ्रीक्वेंसी बैंड होने के कारण इसके सिगनल इमारतों के कहीं भीतर तक प्रवेश कर सकते हैं यानी इंडोर कवरेज के मामले में यह लाजवाब है। इसलिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को घनी आबादी के क्षेत्रों और भारी डेटा खपत वाले इलाकों के लिए आदर्श माना जाता है।

मिलेगी शानदार इनडोर और आउटडोर कनेक्टिविटी

दूसरी वजह है इसकी लॉन्ग आउटडोर कवरेज। 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का टावर करीब 10 किलोमीटर तक कवरेज दे सकता है। इसकी कवरेज के कारण ऑपरेटर को कम टावर लगाने पड़ते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आती है। इसलिए कीमती होने के बावजूद

यह बैंड किफायती 5जी सेवाओं के लिए मुफ़ीद है।

दूर-दराज इलाकों में मिलेगा कनेक्टिविटी

भारत जैसे देश में जहां अभी भी बड़ी संख्या गांवों में रहती है वहां 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की विशाल कवरेज, ग्रामीण भारत को कनेक्ट करने में मदद कर सकती है। यानी 5G केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगी। गांवों में भी इसका फायदा पहुँचना निश्चित है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को, दूर-दराज के ग्रामीण और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करने वाला बताया था।

क्यों बेहतर है 700MHz सपोर्ट

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण है डेटा ट्रैफिक हैंडलिंग में इसकी महारत। यह बैंड स्टैंडअलोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है।



संपादकीय



विचाराधीन कैदियों की रिहाई की बने राह

अदालतों में चल रहे मुकदमों और जेलों में बंद गरीब कैदियों की मदद के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। कानूनी सहायता से जुड़े हुए जजों की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विचाराधीन कैदियों के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) की तर्ज पर ईज ऑफ जस्टिस यानी न्याय की सुगमता भी जरूरी है। कानून मंत्री किरेन रिजजू, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और अन्य जजों ने भी गरीबों को जल्द न्याय देने और कैदियों की रिहाई की बात कही। संविधान के अनुसार गरीब-अमीर सभी बराबर हैं, तो फिर अमीरों की तरह गरीबों को भी जल्द न्याय मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार के तहत लोगों को जल्द न्याय मिलना जरूरी है। इसके बावजूद देश में लगभग 4.88 लाख लोग जेलों में बंद हैं, जिनमें 3.71 लाख विचाराधीन कैदी हैं। इनमें से अधिकतर गरीब, अशिक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों से हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में भारत के लोगों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, लेकिन आजादी के बाद पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में औपनिवेशिक मानसिकता खत्म नहीं होने से विचाराधीन कैदियों का मामला नासूर-सा बन गया। इन वक्तव्यों तथा पहली बार आदिवासी समुदाय से किसी व्यक्ति, वह भी महिला, के राष्ट्रपति बनने से उम्मीदें बढ़ी हैं। इस संदर्भ में तीन जरूरी पहलुओं को समझना जरूरी है- (1) पुलिस द्वारा बेवजह और गैर-जरूरी गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर किसी भी व्यक्ति को आठ घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है। लोगों को पुलिस कब, क्यों और कैसे गिरफ्तार करे, इसके लिए भी कानूनी प्रावधानों के साथ सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले हैं। जिन मामलों में सात साल से ज्यादा की सजा हो, आरोपी के भागने की आशंका हो, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती हो और हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी हो, उन्हीं मामलों में गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन इन नियमों को अनदेखा कर पुलिस द्वारा मनमाने तौर पर गिरफ्तारी विचाराधीन कैदियों की समस्या का सबसे बड़ा मर्ज है। गिरफ्तारी के बाद जमानत का नियम है और जेल भेजना अपवाद है। (2) थकी हुई न्यायिक व्यवस्था। पुलिस की एफआइआर और स्टोरी पर आखंड मुद्द कर भरोसा कर ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट आरोपी को जेल भेजने का आदेश पारित कर देते हैं। इसलिए जेलों में बंद कैदियों के मर्ज के लिए पुलिस से ज्यादा मजिस्ट्रेट और जजों की जवाबदेही है। (3) अंग्रेजों के जमाने के दो शताब्दी पुरानी पुलिस जांच और फौजदारी कानून। तकनीकी विकास के साथ कंप्यूटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गये हैं। दूसरी तरफ सीआरपीसी कानून के तहत पुलिस जांच और साक्ष्य कानून के तहत सबूतों को जुटाने का सिस्टम ब्रिटिशकालीन ही है। इस वजह से पुलिस जांच के बाद लंबे-चौड़े आरोप-पत्रदायर करने का चलन खत्म नहीं हो रहा। इसलिए गवाहों की लंबी सूची और मोटी फाइलों के बोझ से दबी अदालतों से फैसला और न्याय की बजाय लंबी तारीख मिलती है। दूसरी तरफ रईस और रसूखदार लोगों को साम, दाम, दंड और भेद के इस्तेमाल से जल्द न्याय मिल जाता है। ऐसे में न्याय के महंगा होने के साथ लोगों में असमानता भी बढ़ गयी, जिसके लिए प्रधान न्यायाधीश ने चिंता और बेचैनी जाहिर की है। पुराने कैदी रिहा हों और नये कैदियों की आमद कम हो। इन पहलुओं से विचाराधीन कैदियों के मर्ज को दुरुस्त करने के लिए रोडमैप बनाने के साथ कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के हाल के तीन अहम फैसलों को पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, तो इस मर्ज को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। पहला, सीआरपीसी कानून की धारा 41 के तहत संदिग्ध या आरोपी को पुलिस जांच में बुलाने से पहले नोटिस देना जरूरी है। अगर आरोपी हाजिर होता है, तो फिर शिकायत या संदेह के आधार पर उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अगर नोटिस के तहत कोई व्यक्ति हाजिर नहीं होता, तो भी अदालत से वारंट हासिल करने के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के नये फैसले में दिये गये जरूरी दिशानिर्देश के अनुसार जमानत की अर्जी को दो सप्ताह में और अग्रिम जमानत की अर्जी को छह सप्ताह में निपटाना चाहिए।

पूर्व IAS रामविलास की पत्नी कुसुम यादव की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव की पत्नी कुसुम यादव के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि कुसुम यादव जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। बार बार विजिलेंस को

मेल भेजकर समय मांग रही हैं। वह विजिलेंस के सामने पेश नहीं होना चाहती हैं। जबकि विजिलेंस ने उन्हें जून महीने में पूछताछ के लिए नोटिस दे दिया था। वहीं, कुसुम यादव की तरफ से कहा गया कि लखनऊ में उनके मकान के डिमोलिशन के नोटिस आ गए हैं। अभी वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चक्कर काट रही हैं।

इस वजह से वह विजिलेंस के सम्मुख पेश नहीं हो पा रही हैं। कुसुम यादव की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि विजिलेंस उनको कभी भी गिरफ्तार कर

सकती है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए और वे विजिलेंस के सम्मुख अपना बयान दे सकें। जबकि उनके पुत्र व पुत्री ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं।

रामविलास यादव ने अपने बयान में विजिलेंस के सामने कहा था कि उनकी पत्नी ही सारे हिसाब किताब रखती हैं। इसी वजह से विजिलेंस उनको पूछताछ के लिए बार बार नोटिस दे रही है। विजिलेंस को रामविलास यादव के पास आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं।

समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट समिति की हुई बैठक

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखण्ड राज्य में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की तीसरी बैठक नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में हुई। मा0 न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में समिति के सदस्य मा0 न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह, आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त), सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय, श्री मनु गौर, सामाजिक कार्यकर्ता और सदस्य सचिव अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित थे।



आप डेलिगेशन ने पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज को सौंपा ज्ञापन

पंचायत चुनाव में पुरानी रोक हटाकर आदेश लागू होने की तिथि से 9 महीने बाद की कट ऑफ डेट तय करे सरकार: जोत सिंह बिष्ट

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पार्टी के एक शिष्टमंडल ने आज पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने पंचायती राज मंत्री से मांग की है कि उत्तराखंड सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में दो से अधिक संतान वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार उस रोक को हटा कर आदेश लागू होने की तिथि से 9 महीने बाद की कट ऑफ डेट तय करें। जिनका कट ऑफ डेट के बाद तीसरी



संतान होगी उनको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए।

उससे पहले दो से अधिक संतान वालों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित ना किया जाए। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने आम

आदमी पार्टी के शिष्टमंडल को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जोत सिंह बिष्ट के साथ डॉ0 आर पी रतूड़ी, सी पी सिंह, सुरेश चंद्र बिष्ट, सुधा पटवाल और सुशील सैनी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के डॉक्यूमेंट्री फिल्म व पुस्तक “वॉकिंग टू द गॉड” का किया विमोचन

यूटीडीबी ने ट्रेक द हिमालया के साथ मिलकर ऐतिहासिक कदम उठाया : सतपाल महाराज

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में चारधाम यात्रा के पैदल मार्ग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म व पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन विकास परिषद् द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के अन्तर्गत स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वालों को भी सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद् (यूटीडीबी) ने ट्रेक द हिमालया के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। इसके तहत विशेषज्ञों के 25 सदस्यीय दल ने चारधाम ट्रेक पर पुराने मार्गों को खोजने के लिए 1170 किलोमीटर का सफर तय किया। अभियान के तहत 25 सदस्यों की विशिष्ट टीम ने 51 दिनों तक पुराने चार धाम और शीतकालीन चार धाम मार्ग को खोजने का काम किया। इस पूरे अभियान पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के साथ यात्रा मार्ग पर आधारित पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड का प्रकाशन संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस दल को 25 अक्टूबर, 2021 को उनके द्वारा रवाना किया गया था। दल का यह प्रयास निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के पर्यटन के लिये सराहनीय पहल है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्राचीन चारधाम यात्रा पर बनी डॉक्यूमेंट्री तथा पुस्तक हमारी सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे हमारी चारधाम यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड को एक नई पहचान मिलेगी। इस विशेष अभियान का उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता फैलाने, होमस्टे, ट्रेकिंग, स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और मूल रोजगार को बढ़ावा देने के साथ मूल्यवान इतिहास, परंपराओं और समृद्ध संस्कृति को मजबूत करना था। इस अभियान के जरिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी संग्रहित हुआ है, जो भविष्य में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने व पलायन रोकने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना की मूल अवधारणा में पर्यटन क्षेत्र को राज्य की आर्थिकी का मुख्य आधार माना गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व आईएएस अधिकारी आराधना जौहरी द्वारा लिखित पुस्तक वियॉड द मिस्टी वेल, टैम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखण्ड का



उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पुस्तक भी देश विदेश में उत्तराखण्ड के पौराणिक दिव्य मंदिरों मनोरम दुर्लभ स्थलों का प्रमाणिक परिचय देने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम इस वर्ष हमारे लिये किसी चुनौती से कम नहीं थी, दो साल बाद शुरू हुई इस यात्रा में 30 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा पर आये। कपाट खुलने के समय तो यह संख्या एक दिन में 20 से 25 हजार तक रही। यह हमारे पर्यटन के लिये शुभ संकेत है। चारधाम यात्रा मार्गों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये हमारे प्रयास निरन्तर जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। 5 नवम्बर 2021 को केदारनाथ यात्रा के समय प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया था। केदारनाथ पुनर्निर्माण के साथ ही बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसके लिये 265 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये गये हैं। केदारनाथ हेतु केबल कार की योजना कार्य चल रहा है। भारत माला योजना की भांति

पर्वतमाला योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक लाभ राज्य को मिल रहा है। कुमायू क्षेत्र के प्राचीन मन्दिरों को भव्य बनाने के लिये मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन की शुरुआत की जायेगी, चार धाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना, डोईवाला-यमुनोत्री रेल परियोजना के साथ दिल्ली देहरादून एलेवेटेड रोड राज्य के पर्यटन को नई दिशा देने का भी कार्य करेंगे, इसमें हवाई यात्रा से भी कम समय दिल्ली जाने में लगेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कांड यात्रा में भी लाखों श्रद्धालु आये। कांड यात्रा की व्यवस्थाओं के हरिद्वार के साथ ही इससे जुड़े जनपदों के लिये बजट की व्यवस्था की गई है। इससे इस यात्रा को बेहतर ढंग से संचालित किये जाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। हमारे चार धाम पर्यटन स्थलों पर व्यवस्थाएँ सुविधाजनक होगी तो लोग यहां बार बार आने का मन बनायेंगे। इस दिशा में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी राज्य के पर्यटन की बेहतर की लिये अपना योगदान

देना होगा। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता पखवाड़े में सराहनीय योगदान देने वालों के साथ ही पुस्तक की लेखक पलोमा दत्ता तथा ट्रेक द हिमालया के सदस्यों को भी शुभकामनाये दी। मुख्यमंत्री ने जिन्हें सम्मानित किया उनमें नगर पालिका परिषद् अगस्त्यमुनि, रामनगर व शिवालिक नगर हरिद्वार, होटल रेस्टोरेट ऐशोशियेशन, बेस्ट बेरियर सोसाइटी आदि के सदस्य शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने उन्हें हर घर झंडा योजना के तहत राष्ट्रीय ध्वज भी प्रदान किया।

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें स्वच्छता को संस्कार बनाना होगा। इसे अपने मनोभाव से जोड़ना होगा। यह मनोभाव अपने घर के साथ ही वार्ड, शहर और प्रदेश तक की स्वच्छता के प्रति होना चाहिए। यदि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेंगे तो बीमारियां दूर रहेंगी और बीमारियों पर होने वाला खर्च भी बचेगा। जिस तरह कोरोना काल में पर्यावरण मित्रों ने बेहतर काम किया, उसी प्रकार स्थानीय व वार्ड स्तर पर स्वच्छता समितियां बनाकर हर नागरिक को स्वच्छता अभियान से जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) ने ट्रेक द हिमालया के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों को पुराने समय की यात्रा के रोमांच के साथ ठहराव स्थलों के इतिहास से रूबरू कराना है। पुराने समय के रूट पर चलने वाली पैदल चारधाम यात्रा से स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यात्रा मार्ग को पुनर्जीवित करने के बाद इनके आसपास पड़ने वाले गांवों में होमस्टे खोलने, पहाड़ी व्यंजनों के स्टॉल खोलने आदि कार्यों से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश के बारह ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की सुगमता के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार की जा रही है।

सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग द्वारा चारधाम के पौराणिक पैदल ट्रेक की खोज के लिए एक अभियान शुरू किया था। पूरे अभियान की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी से तैयार डॉक्यूमेंट्री फिल्म व यात्रा मार्ग पर आधारित पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड के विमोचन से पर्यटन क्षेत्रों को पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री जी के निर्देशानुसार हम उत्तराखण्ड पर्यटन को बढ़ावा देने व अंतरराष्ट्रीय मानचित्र में पहचान दिलाने के

लिए लगातार काम कर रहे हैं। यूटीडीबी की ओर से चलाए गए स्वच्छता पखवाड़े का उद्देश्य देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड में स्वच्छ और सुंदर वातावरण उपलब्ध कराना था। विभाग की ओर से चलाए गए स्वच्छता पखवाड़े में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट निपटान से संबंधित सर्वोत्तम तकनीकों के बारे में राज्य भर में होमस्टे मालिकों, होटल व्यवसायियों और स्थानीय समुदायों को जागरूक किया गया। इसके अलावा प्रदेश के धार्मिक स्थलों को भी स्वच्छ बनाए रखने के लिए पर्यटन विभाग निरंतर प्रयासरत है।

इस अवसर पर अपर सचिव पर्यटन सी रविशंकर, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहसिक पर्यटन कर्नल अश्विनी पुंडीर, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पूजा गब्रवाल, निदेशक इंफ्रास्ट्रक्चर ले. कर्मांडर दीपक खंडूरी, निदेशक वित्त जगत सिंह चौहान, अपर निदेशक श्रीमती पूनम चंद, अपर निदेशक विवेक सिंह चौहान, उप निदेशक योगेंद्र सिंह गंगवार, वरिष्ठ शोध अधिकारी एस एस सामंत सहित पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।



दैनिक न्यूज़ वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड,
मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक
मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स,
अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित
एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला,
देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी

दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTIH/2012/44094

वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून
न्यायालय मान्य होगा